

Sustainability Transitions in Rajasthan

Exploring Diverse Pathways



Sustainability Transitions in Rajasthan: Exploring Diverse Pathways

The Living Farm Incomes team at the Institute of Rural Management Anand (IRMA) has been engaging with Civil Society Organisations (CSOs) in Gujarat and Rajasthan to explore together the challenges and opportunities for sustainable transitions. Creating an enabling supportive ecosystem for sustainable agriculture has meant work along four themes. We seek to “rethink agricultural knowledge” by understanding formal agricultural research systems and their sustainability orientations through a close look at their curriculum and institutional mechanisms. We undertake field visits to learn from, and document, tacit knowledge on the processes and pathways as ‘champion farmers’ enable transitions to agroecology and natural farming. We provide capacity building workshops on specialised themes such as [systems thinking for sustainable food systems](#) and support young interns with opportunities to work with CSOs engaged in agroecological transitions. This could include surveys on perceptions of organic farming across districts. We regularly share our findings through multistakeholder forums to create [learning alliances](#) at the state and national level to build policy dialogues and uptake by encouraging academicians and practitioners to work together at every stage of shaping these transitions.

More details of our work on managing sustainable transitions can be found through our 31 blogs on [managing sustainable transitions](#) (including a compendium [Shifting Grounds](#)) as well as our [publications](#). This intermediate publication of four blogs reflects some of our team’s visits to Dungarpur, Barmer (including Thar) and Sirohi facilitated by the partners of the National Coalition for Natural Farming (Rajasthan). We hope that the blogs will inspire greater documentation of ongoing initiatives, including challenges in enabling transition, and provide opportunities for dialogue and cross learning among farmers, CSOs, agriculture researchers, government departments, academia and citizens interested in creating sustainable futures for farmers and consumers. We thank Avisha Jain and Rohit Parakh of NCNF, the host organisations and the NCNF steering committee members for their suggestions and for facilitating these visits and for being more than willing partners in creating a learning alliance and we hope to continue to learn together.

Shambu Prasad, C.

March 2023

मरुधरा में जैविक खेती की ओर बढ़ते महिलाओं के कदम

- शुभा खड़के

खेती में महिलाओं का योगदान सर्वविदित है, खेत की तैयारी, बुवाई, निंदाई, गुड़ाई से लेकर फसल कटाई और सफाई तक सभी में महिलाओं की भागीदारी होती है। राजस्थान के सन्दर्भ में बात की जाये तो यहाँ महिला किसानों द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कृषि के नए और रचनात्मक तरीकों को अपनाया जा रहा है। वे जैविक खेती की ओर भी कदम बढ़ा रही हैं। राजस्थान में सीकर जिले के झीगरबाड़ी गांव की श्रीमती संतोष पचार को 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। उनके गाजर के बीज के नए प्रयोग से गाजर का न सिर्फ उत्पादन बढ़ा है बल्कि वो अधिक मीठी हुई है। श्रीमती संतोष खेती में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी तरह राज्य के अन्य भागों में भी महिलाएं जैविक खेती के लिए प्रयासरत हैं।

प्रस्तुत आलेख मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पीडो संस्था के कार्यक्षेत्र डूंगरपुर और पश्चिमी राजस्थान में उन्नति संस्था के कार्यक्षेत्र बाड़मेर में जैविक खेती में महिलाओं की भागीदारी को साँझा कर रहा है।

“जो हम नहीं खाते वे ग्राहकों को कैसे खिलाये” - लीलाबेन हूरजीभाई, डूंगरपुर

लीलाबेन जन शिक्षा एवं विकास संगठन (People's Education and Development Organization - PEDO) की सदस्य हैं और संस्था से ही उन्होंने जैविक खेती के बारे में जाना।

PEDO एक स्वैच्छिक संगठन है, जो 1980 से गरीब समुदायों के साथ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है। संगठन मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण, सतत आजीविका को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्वच्छता और स्वच्छ जल, लघु सिंचाई प्रबंधन, खेती विकास, पंचायती राज संस्थाओं का मजबूतीकरण आदि मुद्दों पर दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर क्षेत्र में कार्यरत है। PEDO का महिला महासंघ मॉडल बहुत मजबूत है और उनका सभी महिलाओं के साथ अच्छा जुड़ाव है। उनके कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास से भरी महिलाओं और विकास पर उनके विचारों को जानने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि संस्था का समुदाय से गहरा जुड़ाव है।



इसी महासंघ से जुड़ी है लीलाबेन। वे डूंगरपुर से 18 किलोमीटर दूर रातापानी गांव में रहती हैं। उनके पास कुल 5 बीघा ज़मीन है जिसमें 1-1.5 बीघा ज़मीन में वे सब्जियां उगाती हैं, बाकि में वे घर के लिए अनाज उगाती हैं। पहले वे रासायनिक खाद और दवाओं का उपयोग करती थीं परन्तु संस्था ने जब रासायनिक दवाओं से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में बताया तो उन्होंने जैविक सब्जियां उगाना शुरू किया। वह संस्था के

मार्गदर्शन में पिछले 5-6 वर्षों से जैविक सब्जियां उगा रही हैं। वे पौध नर्सरी खुद तैयार करती हैं और बीज उपचार

से लेकर सब्जियों की तुड़ाई तक समय समय पर जीवामृत , जैविक खाद , ब्रम्हास्त्र आदि जैविक दवाओं और खाद का उपयोग करती है। लीलाबेन बुवाई के समय से थोड़ा पहले ही सब्जियों की बुवाई कर देती है। जिससे मार्केट में सब्जियां आने के पहले इनकी सब्जियां आ जाती है , और अच्छा भाव मिल जाता है।

मुख्य बात यह है कि उनके पति प्रतिदिन सुबह डूंगरपुर की 4 से 5 कॉलोनियों में बंधे हुए ग्राहकों के घर सब्जियों की होम डिलीवरी करते हैं। हर शाम को लीला

बेन सब्जियां तोड़ कर रखती है और उनके पति सुबह 6 से दोपहर 2 बजे सब्जियां देने जाते हैं। प्रतिदिन लगभग 2000 रुपये की सब्जियां बेचते हैं उसमें 200 रुपये तो पेट्रोल के लिए खर्च हो जाते हैं। वे और उनके पति बेहतर योजना के साथ सब्जियां लगाते हैं जिससे ग्राहकों को पूरे वर्ष सभी मौसमी सब्जियां मिलती रहती है।



लीलाबेन ने सब्जियों के अपने व्यवसाय के बलबूते पर अपने एक बेटे को वेटेनरी डॉक्टर बनाया है, दूसरा एग्रीकल्चर में M.Sc कर रहा है और बिटिया B.Sc, बी.एड कर चुकी है। लीलाबेन कहती है कि जैविक खेती में मेहनत ज्यादा है पर जब बात स्वास्थ्य की होती है तो उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। लीलाबेन से चर्चा करना बेहद उत्साहपूर्ण था।

पीडो ने जब काम शुरू किया था तब इस क्षेत्र में लोग बीटी कॉटन लेते थे, परन्तु इसमें खर्चा अधिक था और जमीन की उर्वरकता भी धीरे धीरे कम हो रही थी इसलिए संस्था ने लोगो को हल्दी लगाने के लिए प्रेरित किया। संस्था ने अपने परिसर में जैविक हल्दी प्रसंस्करण यूनिट "माही" को शुरू किया, आज लगभग 1500-1600 महिलाएं इस यूनिट से जुड़ी हुई हैं। ये पूरी तरह जैविक पद्धति से हल्दी उगाती हैं। संस्था बाजार भाव से महिलाओं को 5 रुपया प्रति किलो ज्यादा भाव देकर हल्दी खरीदती है। प्रति वर्ष लगभग 10 से 15 टन हल्दी खरीदी जाती है फिर उसको प्रोसेस कर माही ब्रांड के साथ रिटेल में बेचा जाता है।



गत कुछ वर्षों से संस्था निरंतर प्रयास कर रही है कि महिलाएं जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ें। इसमें महिला संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। लीलाबेन की तरह लगभग 10000 से अधिक महिलाएं संस्था से जुड़ी हैं।

"हम बिना ज़हर की खेती करते हैं" - हीरादेवी, बाड़मेर

रेतीला पश्चिमी राजस्थान ढाणियों में बसा हुआ है। ऐसी ही एक ढाणी कबीर नगर में रहने वाली हीरा देवी गत एक वर्ष से जैविक पद्धति से सब्जियाँ उगा रही हैं। वे उन्नति संस्था द्वारा २०१७ में गठित जय भीम महिला किसान संगठन (JBMKS) की सदस्य हैं। उन्नति एक स्वैच्छिक संगठन है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सुशासन, महिला सशक्तिकरण आदि मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं।

जयभीम महिला किसान संगठन (JBMKS) में पाटोदी संकुल के 25 गाँवों की 700 और सिंदरी संकुल के 25 गाँवों की 700 महिलाएँ सदस्य हैं। सभी अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएँ हैं। इस संगठन का उद्देश्य महिला किसानों को पहचान देना और महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायता करना है। संगठन ने उन्हें उन्नत कृषि पद्धतियों के लिए भी सहयोग दिया है। संस्था ने अनुदान सहायता के साथ संगठन को ट्रैक्टर, ट्रॉली, पानी के टैंकर और छोटे कृषि उपकरण प्रदान किए। संगठन के सदस्यों ने कुछ दरेंतय कीं और इन निश्चित दरों पर ये उपकरण सदस्यों को किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं। इससे महिलाओं को जैविक खेती में सहयोग मिल रहा है।

माल्टेसर इंटरनेशनल और जीआईजेड (GIZ) पाटोदी के 25 गाँवों और सिंदरी के 25 गाँवों में भोजन और पोषण के लिए उन्नति संस्था को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इन गाँवों में उन्नति जैविक खेती पर काम कर रही है। "बागवानी विकास और सब्जी की खेती" परियोजना के तहत उन्होंने 132*132 फीट में महिलाओं को 70 पौधे प्रदान किए। 70 पौधों में 42 पौधे बेर, 4 सुरजना, 21 गुंदा और 3 खेजड़ी हैं। 3-5 साल के अंदर सभी पौधे फल देने लगेंगे।



बीच-बीच में महिलाएं मौसमी सब्जियाँ ले रही हैं। यह सूखा क्षेत्र है इसलिए पोषण सुरक्षा और फल बेचकर अतिरिक्त आय के लिए संस्था इस परियोजना को लागू कर रही है।

इस परियोजना की लाभार्थी हीरा देवी ने बताया कि उसके पास 5 बीघा रेतीली जमीन है इसलिए वर्षा आधारित कृषि ही एक मात्र संभव विकल्प है। वे आम तौर पर केवल अपने उपभोग के लिए बाजरा, मूंग, मोठ और ग्वार उगाते हैं। बिक्री के लिए कोई अधिशेष नहीं होता है। जय भीम महिला किसान संगठन की बैठकों के दौरान उन्होंने जैविक खेती मतलब "बिनाजहर की खेती" के बारे में जाना। अगस्त 2021 में संस्था ने उन्हें 70 पौधे उपलब्ध कराए। संस्था की टीम के मार्गदर्शन में वह मौसमी सब्जियाँ उगा रही हैं। वह बीज उपचार, बीजामृत, जीवामृत और अन्य जैविक खाद के बारे में बता रही थीं। पहले उनको सब्जियाँ खरीदनी पड़ती थी लेकिन पिछले

एक साल से उन्हें ताजी सब्जियां मिल रही हैं जिसे उन्होंने अपने पड़ोसियों में भी बाँटा है। उन्होंने भिंडी, ग्वार, बैंगन, पालक, टमाटर आदि उगाए हैं।

इसी संगठन की सदस्य श्रीमती ममता देवी हेमाराम ने जैविक खेती के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उनकी 4 बीघा जमीन में 3 बीघे में बाजरा और 1 बीघा में मोठ उगाया था। पहले वे एक बीघा जमीन में वह केवल 10 किलो मोठ लेती थी लेकिन इस साल उसे 50 किलो मोठ मिला। उन्होंने नियमित रूप से खाद और जीवामृत का ही उपयोग किया और वे बिना जहर की खेती के अपने प्रयोग से काफी खुश हैं।

रेनफेड क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है ऐसे में जैविक खेती के लिए बढ़ती जागरूकता और महिलाओं द्वारा किये गए प्रयास निश्चित ही उल्लेखनीय हैं।

राजस्थान में जैविक खेती का परिदृश्य

राजस्थान में जैविक खेती की नीति तो 2017 से है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में "खेती में जान तो सशक्त किसान" योजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना राज्य के तीन जिलों टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में शुरू की गई थी परन्तु वर्ष 2020-21 में 15 जिलों तक बढ़ाई गई।

इस योजना में किसानों को उपकरणों पर अनुदान दिया जाता है। साथ ही प्राकृतिक खेती में रुचि रखने वाले किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से होने वाले नुकसान के साथ-साथ प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। कम लागत वाली खेती की तकनीक और जीवामृत, बीजामृत, घनामृत आदि का उपयोग भी सिखाया जा रहा है।



यदि इस योजना में महिला किसानों को वरीयता दी जाय तो निश्चित ही इसका फैलाव तेजी से होगा। चर्चा के दौरान ये स्पष्ट प्रतीत हुआ की महिलायें अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होती जा रही है अतः खेती में जैविक पद्धतियों को अपनाने में उनका रुझान भी अधिक है। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा बनाये गए महिला संगठन सशक्त रूप से आजीविका और महिला मुद्दों पर कार्य कर रहे है ऐसे में उनके माध्यम से महिलाओं में जैविक खेती की अलख जगाना आसान है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में महिलाएं ही जैविक खेती की मशाल आगे ले जायेंगी।

शुभा खड़के लिविंग फार्म इनकम प्रोजेक्ट, इरमा (IRMA) में प्रोग्राम और आउटरीच कन्सल्टन्ट हैं।

Champion farmers and keen stakeholders: transitioning to natural farming in the Thar

- Abhishek Saxena

The Government seeks to promote more bioinputs and natural farming practices as is evident in the latest budget speech. farmers who are innovative and early adopters can be a great resource towards this goal. Rajasthan's novel attempt to upscale natural farming through Gram Panchayat plans can benefit through documenting innovative practices of champion farmers.

The Natural Farming Thrust

The announcement of the Finance Minister of a scheme to enable states to transition to sustainable agriculture has received a boost through [the PM-PRANAM](#) yojana, the latest in line of the previous schemes aimed at pushing for sustainable agricultural practices such as Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) that promotes farming through Bhartiya Prakritik Krishi Paddhati Program (BPKPP). Civil Society Organisations have independently collaborated to promote agroecology-based farming. [The National Coalition for Natural Farming \(NCNF\)](#) is one such coalition formed in 2020-21 with five state chapters including Rajasthan. In Rajasthan NCNF partners have sought to integrate natural farming into the gram panchayat development program (GPDP). Rajasthan has 10 agroclimatic zones and correspondingly crops, farming practices, and resource availability with the farmers. A few vignettes of natural farming practices in the 'arid western plains' that form part of the desert region known as Thar, are presented.

Farmer to farmer learning and innovation

Jogaram of Hathi Tala village in Barmer used to work in a stone quarry. Like most people involved in stone mining and cutting he suffered from Silicosis. This is when he returned to farming. He grows pearl millet (*bajra*) and psyllium (*isabgol*) as the principal crops with vegetables such as brinjal, legumes such as green gram (*mung*) and *moth* and some locally used herbs and condiments like *ber*, *kair* and *sangri*. The highlight of his farm is the variety of *bajra* and the *isabgol* that he grows. Jogaram shares that he brought the seeds of *bajra* and *isabgol* from his relative and crossed them with the variety that he was growing on his field. This was few years back, when he was still using chemicals on his field and was in the process of transition. He shifted to natural farming around 2019 and uses the castor, neem and other weeds growing on his field, along with the cow urine and dung, to make bioinputs. Now, when he farms naturally, his *bajra* grows to a height of 12-14 feet having a 3-4 feet long grain ear! Even



the yield per *bigha* (local unit of land measurement with 6.20 *bigha* being 1 ha) of land is more for this cross-pollinated variety at 7 Qt (as compared to 4 Qt for the *desi bajra* that farmers grow). Jogaram does not sell this bajra at the farmers' market yard (*mandi*) at Barmer. Instead, he sells it at a very high premium (Rs. 800/Kg, as compared to Rs. 25-35/Kg of pearl millet sold at the *mandi*) to anyone who is willing to buy. It was a similar story with the psyllium, however that was sold at the farmers' market, even as his cross-pollinated variety stood out in the field as compared to the normal variety that he had also planted. Even though Jogaram owns 10.75 ha of land and has access to irrigation, which many others in the regions are not fortunate enough to have, his experience of turning to natural farming and experimenting with seeds obtained from other farmer can be a lesson.

The significance of local support ecosystem



Ganesharam (Ganesh) is a community resource person with the RCD Social Service Society (RCD) in Aati *gram panchayat*, Barmer. He comes from a farming background and is knowledgeable about *desi* farm inputs and pesticides. The 5 *bighas* of land that he has is divided into *vadis* or

bagiyas where his parents grow vegetables such as brinjal, radish, carrot etc. apart from the land where he had sown *bajra* and *isabgol*. The 'wasteland' that his farmland consisted of is where a treasure of trees, weeds and grasses existed. These were used in making seed treatment concoctions, pesticides etc. A few commonly known included *neem*, castor and milk weed. He prepares vermicompost for his own use and showed us the vermicompost unit that he had at his place established with the help of RCD.

Ganesh's experience has led to another vermicompost unit managed by a women's SHG. This unit was supported by NABARD. It yields close to 1 quintal of compost from a single pit. There are 12 such pits and it takes 3-4 months to convert cattle dung to compost, under conditions of 60% moisture, and optimum earthworm activity. The local ecosystem consisting of RCD and NABARD have been able to promote vermicomposting in the region to a large extent, demonstrating the significance of support ecosystems.



Engaging stakeholders through GPDP: The significance of NCNF's interventions



NCNF's focus on GPDP for inclusion of 'promotion of ecologically sustainable practices' in the plan has huge significance in the region. Interacting with GPDP can help include local knowledge and practices and come up with bioinput based farming that can be sustained using the local flora and fauna with minimum import from outside. This would require collaboration between various stakeholders. Toward this end, engaging with *gram panchayats* through the GPDP seems a promising step taken by NCNF. It helps to scale up the initiatives taken by individual CSOs in two ways *viz.* collectively researching and designing interventions to be implemented through *panchayats*, and utilising the resources allocated to the *panchayats*. Next, and more importantly, it can help leverage the strong on-ground knowledge and data that exists with the *panchayat*, on farmers, their landholding, popular practices, crops, livestock, other flora and fauna, and post-harvest consumption and marketing behaviour of the farmers. Research institutions and local agricultural universities can collaborate to help in the documentation of these knowledge, practices and behavioural trends to inform relevant policies and initiatives. Creating participatory forms of co-learning initiatives is important to recognize the embedded wisdom in the community and possibilities of innovation through wider interactions. This point is [illustrated through the involvement of student interns](#) (as part of the LFI internship) in collecting ground-level knowledge, such that the experiences also serve to expand their own educational horizons and aspirations. Given the nascent stage of transitions in the area, in-depth field documentations can also help raise more critical questions. Some of the most prominent questions that emerge are: how is the livelihood of farmers impacted by a shift to natural farming? Whether the changes in farming methods have led to crop diversification and has their diets been impacted by expected demand of particular crops? What is the effect of natural farming practices on the larger ecology. These are generative questions that will benefit from increased dialogues and collaborations between CSOs, educational institutions, farmers and government agencies and it is hoped that the GPDP would explore these dimensions in their plans. A few promising pilots can serve as models for similar initiatives in other districts and states too providing insights for ground level implementation of PM_PRANAM.

Abhishek Saxena is a Research Fellow in the project and also pursuing his doctoral research at IRMA.

मरुस्थल में संगठित होती महिला किसान

- शुभा खड़के

रेत के बवंडर और उनके बीच चलती महिलाओं की बैठक, जहाँ महिलाएं घूँघट में बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी खेती और उससे जुड़ी चुनौतियों पर बात करती हैं। ये विशेष दृश्य पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के पाटोदी ब्लॉक का है, जहाँ जय भीम महिला किसान संगठन की सदस्य अपनी बैठकों में खेती और आजीविका के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती हैं। वर्तमान में जहाँ महिला किसान खेती में अपनी पहचान के लिए प्रयासरत हैं वही पश्चिमी राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला किसानों का संगठन निश्चित ही सराहनीय पहल है।

पश्चिमी राजस्थान में आज भी महिलाएं घूँघट करती हैं, और जब घूँघट में कोई महिला अपने संगठन के बारे में, उसके कार्यों के बारे में बात करती है तो उनके आत्म विश्वास को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। पर इस तरह संगठन बनाना इतना आसान भी नहीं था। उनकी ये यात्रा निश्चित ही प्रेरणादायक है।



महिला किसानों के योगदान को पहचान देता 'उन्नति' का संगठन

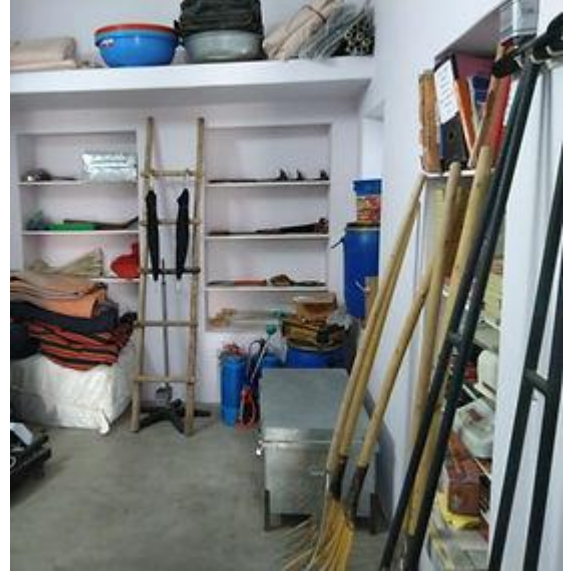
इस यात्रा की शुरुआत 'उन्नति विकास शिक्षण संगठन' के सामुदायिक विकास कार्यों के साथ हुई। 'उन्नति' महिलाओं के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सुशासन, महिला सशक्तिकरण आदि कई मुद्दों पर कार्य कर रही है। महिलाओं के साथ काम करते हुए संस्था ने अनुभव किया कि खेती में उन्नत तकनीक की जरूरत है, महिलाएं खेती में बराबरी से सहयोग कर रही हैं अतः संगठन के माध्यम से कई महिलाओं को एक साथ मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है, रसायन मुक्त खेती की जानकारी दी जा सकती है। रासायनिक उर्वरकों के नुकसान से महिलाओं को अवगत कराया जा सकता है साथ ही कम संसाधनों में भी एक दूसरे की मदद हो सकती है।

जय भीम महिला किसान संगठन का गठन और विकास

इसी उद्देश्य के साथ और खेती में महिला किसानों के योगदान को पहचान मिले इस हेतु से 'उन्नति' ने अपने कार्यक्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में 2017 में जय भीम महिला किसान संगठन (जेबीएमकेएस)" के गठन में मदद की है। पाटोदी संकुल के 25 गाँवोंकी 700 और सिणधरी संकुल के 25 गाँवों की 700 महिलाएँ इस संगठन की सदस्य हैं। सभी 1400 महिला किसान अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएँ हैं। 100 रुपये के सदस्यता शुल्क के साथ ये सभी महिलाएँ इस संगठन की सदस्य हैं।



'उन्नति'
के प्रत्येक
गाँव में
एक ग्राम



स्तरीय संगठन है, जिसमें 18-30 महिला सदस्य हैं। इन सदस्यों में से 2 सदस्यों को खेती साथण (कृषि सखी) के रूप में चुना जाता है। वे अन्य सदस्यों को सहयोग करती हैं और अपने समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये 2 खेती साथण ब्लॉक लेवल समिति में जाती हैं। इस तरह 25 गाँवों में से 50 महिलाएँ ब्लॉक स्तरीय समिति में भाग लेती हैं। पाटोदी के 25 गाँवों की 50 महिलाएँ और सिणधरी के 25 गाँवों की 50 महिलाएँ ब्लॉक स्तरीय समिति में हैं। दोनों संकुल की ब्लॉक स्तरीय समितियाँ हैं और चुनी गई 50 खेती

साथण अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव करती हैं। दोनों ब्लॉक स्तरीय समितियों में संगठन सम्बन्धी सभी निर्णय लिए जाते हैं। इन दोनों समितियों के बैंक खाते हैं जिसके माध्यम से पैसे का लेन देन होता है जैसे कृषि उपकरणों का किराया आदि उसमें ही जमा होता है।

संगठन से सशक्त होती महिला किसान

संगठन को मजबूत करने हेतु 'उन्नति' ने संगठन को कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग से जोड़ा। मिट्टी की जाँच, बीज उपचार तथा तकनीकी जानकारी जैसे जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशक, कम्पोस्ट खाद आदि बनाना महिलाओं को सिखाया। कृषि विभाग की सहायता से मिनी किट, बीज खाद आदि उपलब्ध कराये। इसके साथ ही 'उन्नति' रसायन मुक्त जैविक खेती की पद्धतियों के बारे में जागरूक करने का सतत प्रयास कर रही है।

‘उन्नति’ ने संगठन के कार्य को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से प्रत्येक 5 गांव में दो महिला मैनेजर को नियुक्त किया है। इनका काम खेती उत्पाद खरीदना, मार्केटिंग करना, महिलाओं को तैयार करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करना आदि है। मैनेजर को काम के आधार पर मानदेय दिया जाता है जो लगभग 3000/- प्रति माह है।

“बड़े उपकरण खरीदना हमारे लिए कठिन है ऐसे में संगठन की वजह से खेती के लिए जरूरी उपकरण हमें समय से मिल जाते हैं। हमारे परिवार को भी पता है कि हम संगठन से किराये पर उपकरण ला सकते हैं। यहाँ से हमें अच्छे बीज भी मिल जाते हैं जिससे उत्पादन अधिक होता है। इस से परिवार में भी हमारा सम्मान बढ़ा है।” - ममता देवी

ममता देवी की सास उन्नति से जुड़ी हुई थी अतः वे भी संगठन से जुड़ी। वे बताती हैं कि संगठन निरंतर प्रयास कर रहा है कि महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उनको अपनी पहचान मिले और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से खेती में फायदा मिले। संगठन ने उन्हें उन्नत कृषि पद्धतियों के लिए भी सहयोग दिया है। उन्नति ने अनुदान सहायता के साथ संगठन को ट्रैक्टर, ट्रॉली, पानी के टैंकर और छोटे कृषि उपकरण प्रदान किए। संगठन के सदस्यों ने कुछ दरें तय कीं और इन उचित दरों पर ये उपकरण सदस्यों को किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं। इस से महिलाओं को जैविक खेती में सहयोग मिल रहा है।

उन्नति के पाटोदी कार्यालय में जय भीम महिला किसान संगठन के पाटोदी ब्लॉक स्तरीय समिति का भी कार्यालय है जहाँ संगठन के पास उपलब्ध विभिन्न कृषि उपकरण रखे जाते हैं। संगठन की वार्षिक बैठक में इन उपकरणों को किराये पर देने के लिए दरें निश्चित की जाती हैं।



संगठन के पास दांतली, खुरपी, स्प्रे पम्प, कुदाल, कटर मशीन, कल्टीवेटर, झाल, क्रॉप हार्वेस्टर से लेकर पानी के टैंकर, ट्रैक्टर तक उपलब्ध है। इनकी किराया दर घंटे से लेकर एक दिन के हिसाब से है जो न्यूनतम 10 रुपये से 700 रुपये तक है। इन उपकरणों की संख्या भी वर्तमान की मांग के अनुरूप है। खेती साधन के माध्यम से गांव से महिलाओं की मांग आती है। प्रत्येक गांव का हिसाब रखने की जवाबदारी मैनेजर की होती है।

कदम दर कदम बढ़ता संगठन का कारवाँ

पिछले 5 सालों में उन्नति निरंतर प्रयास कर रही है कि संगठन मजबूत हो हालाँकि अभी भी संगठन अपनी शैशवावस्था में ही है। संगठन के पास लगभग 5 लाख रुपये की राशि है। संगठन के सदस्य अपनी उपज को संगठन को ही बेचते हैं। संगठन अपने सदस्यों को 1 बीघा के लिए बीज के रूप में मूँग 2.5

किलो, मोठ 2.5 किलो और बाजरा 1 किलो उपलब्ध करता है। उत्पादन होने पर सदस्यों को दुगुना अनाज संगठन को लौटाना पड़ता है। अधिक उत्पादन बाजार भाव से संगठन को बेच सकते हैं। संगठन हर उपज की कीमत बाजार

भाव से अधिक देने का प्रयास करता है। ये भाव संगठन की बैठक में सर्वसम्मति से तय किये जाते हैं। इस वर्ष संगठन ने 56 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सदस्यों से मोठ खरीदा है। उसे 60 रुपये प्रति किलो के भाव से बाजार में बेच दिया। इस तरह प्रति किलो पर 4 रुपये का फायदा संगठन को मिला। इस वर्ष संगठन ने 748 किलो मोठ और 110 किलो बाजरा खरीदा। ज्यादा बरसात की वजह से इस वर्ष मूँग नहीं हुआ। इस तरह संगठन की आमदनी उपज बिक्री से होती है साथ ही खेती के उपकरण, ट्रैक्टर, पानी के टैंकर आदि के किराये से भी होती है। सिर्फ पानी के टैंकर से इस वर्ष संगठन ने 60000/- कमाए।

ये तो बस शुरुआत है विगत 5 वर्षों के प्रयासों से अब महिलाएं अपने निर्णय लेने में सक्षम हुई हैं। उनके परिवारों में भी उनकी अहमियत बढ़ी है। अब महिलाएं 'उन्नति' के मार्गदर्शन में किसान उत्पादक संघ में पंजीयन कराना चाहती हैं। संगठन के माध्यम से उपज की खरीद और बिक्री प्रारम्भ हो चुकी है। ये क्षेत्र सांगरी के लिए जाना जाता है। अतः महिलाएं संगठन के माध्यम से सांगरी को थोक में खरीदना चाहती हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देना भी उनकी भविष्य की योजना में शामिल है।



पश्चिमी राजस्थान के दुर्गम क्षेत्र में संगठन के माध्यम से महिलाएं एकजुट होकर सशक्त हुई हैं। छोटी छोटी जोतें, कम पानी, रेतीली जमीन और संसाधनों की कमी के परिदृश्य में महिलाओं का साथ में आना, खेती में एक दूसरे की सहायता करना, खेती के बेहतर तरीकों को सीखना और जैविक खेती की नई नई पद्धतियों को अपनाना, खेती में महिलाओं को मिलती पहचान का एक सुख दसंकेत है।

पश्चिमी राजस्थान की इन महिलाओं ने संगठन बना कर एक बहुत कठिन पड़ाव पार कर लिया है अब निश्चित ही वे आगे की चुनौतियों का भी दृढ़ता से सामना करने के लिए तैयार हैं। संगठन ने इन महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है अतः संगठन के माध्यम से जैविक खेती के बारे में महिलाओं को जागरूक करना आसान है। जैविक खेती के प्रचार प्रसार में महिलाएं महती भूमिका निभा सकती हैं क्योंकि वे अपने परिवार के स्वास्थ्य को ले कर सर्वाधिक सजग होती हैं। ऐसे में सरकार की जैविक खेती सम्बन्धी नीतियों को महिला संगठन के माध्यम से महिलाओं द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। इस दिशा में सरकार, संगठन और आमजन सभी के सम्मिलित और सक्रिय प्रयास अपेक्षित हैं।

शुभा खड़के लिविंग फार्म इनकम प्रोजेक्ट, इरमा (IRMA) में प्रोग्राम और आउटरीच कन्सल्टन्ट हैं।

Transitioning to Sustainability: Vignettes from the Field

- Aneesh Mohan

Centre for microfinance, in collaboration with National Coalition for Natural Farming for the past 2 years has been trying to bring about a sustainable transition in the region of Pindwara. The routes to sustainable transition are plural and diverse and is reflected in the three transition journeys of farmers from Sirohi district in Pindwara, Rajasthan.

Sirohi, sandwiched between the erstwhile kingdoms of Mewar and Marwar, presents a contrast to earlier sustainable transition stories from [Mewar \(Dungarpur\)](#) and [Marwar \(Barmer\)](#). [Centre for microFinance \(CmF\), in Pindwara](#) block of Sirohi, got introduced to the [National Coalition for Natural Farming](#) in 2021 and is promoting sustainable agricultural practices in the region.



Pindwara is semi-humid with a rainfall of 600 – 800 mm. The farmers of Pindwara depend mostly on rainwater, but there has been an increasing trend in irrigating lands through wells/tubewells. About one-third of the population is tribal, mainly, the Garasiyas. Farmers, historically, have used *gobar-khaad* to fertilise their agricultural land but with introduction of chemical fertilisers and the many subsidies, *gobar-khaad* got slowly replaced with chemical-fertilisers. Sirohi is famous for its namesake goat breed, however, the use of goat-faeces in preparation of biologically active recipes like *Jeevamrut* is something that has not yet been fully explored.

CmF has been trying to promote natural farming in this region through support from [Krishi Vigyan Kendra \(KVK\), Sirohi](#) and NCNF. In the absence of a differentiated market for organic or naturally-farmed produce in the district, the reason for transition becomes cost-saving rather than profits. A few vignettes from the field demonstrate a new dawn in Pindwara.

“She wants to join me too” – Dasubai, an inspiration to others



Dasubai is a farmer of the Garasiya tribe from Thandiveri village in Pindwara and stopped using any chemical inputs on her 3 bigha land, for the last three years. Around the same time, she received a training from Krishi Vigyan Kendra (KVK) on producing bio-inputs like *Jeevamrut* and *Khaati Chhas*. In the *Kharif* season, she grows wheat for sale and self-consumption and grows various pulses and corn during *Rabi*. Apart from that, she has many tall papaya shrubs, and is growing brinjal and tomato on her field. She is also raising 3 buffaloes and has 9 goats. She has a borewell at her disposal for irrigation and other purposes.

She procures her seeds from both CmF and KVK, and regularly calls CmF for the deworming and vaccination of her animals. Ever since she switched to using bio-inputs, she has saved a lot of money (estimating around Rs 4000) from not having to use Urea or DAP. Not only that, but she has also found a channel to sell her wheat to the factory workers of the nearby UltraTech Cement Factory.

Her customers are willing to pay a premium as they trust her produce and she sells the wheat at Rs 35 per Kg, compared to the market price which is Rs 20 per Kg. The same, however, is not true for the chickpea she grows, and she is yet to find a more profitable market for it.



Seeing Dasubai's success with bioinputs, her neighbour wants to follow in her footsteps. She was skeptical of her methods initially but after seeing the length and health of her wheat crops, she too is considering using bioinputs.

Kalaram – the Persistent Natural Farming Champion



Kalaram, from Mori village, is not very educated but possesses immense farming knowledge. Two years back he started using *Jeevamrut* on his 2 *bigha* land (1.2 acres) after he started seeing cracks on his land. Although, he has been making use of *gobar-khaad* for even longer. While his wife is employed in MGNREGA and works as a wage labourer, he is more active on the field and prefers to spend at least an hour every day in his farm. Their family farms entirely for sustenance and also has three cows for their own use. They get their seeds from the nursery in Pindwara. Last year, they also got a tubewell to quench their water needs and he plans on adding solar panels for it as currently the electricity is erratic. His family is food secure and the only things they purchase from the market are turmeric and salt.

He came across CmF and they later took him for a training at KVK, Sirohi, where he learnt how to make *Jeevamrut* and *Khaati Chhaas*. Ever since switching to bio-inputs, the effort he puts on the field has increased but he has no complains and instead finds it ‘relaxing’. Kalaram is a ‘Resource Farmer’ for CmF and his field is often used for exposure visits by other farmers.

Basubai’s ongoing journey from an FPO staff to natural farming



Basubai has been a member of the Samruddhi FPO for the past six years. She has 1.5 *bigha* land. There are five members in her family. Both her husband and son used to be employed in silica mining. However, her husband developed silicosis and that severely impacted their finances. She took a loan of Rs 30,000 from RMGV Bank and is repaying Rs 2030/month.

She has 3 cows, 3 buffaloes, 3 goats (which she had bought 12 months back

for about Rs 3000 each). She hopes to sell them at Rs 10,000 each. Earlier, she used to sell her goats to Samruddhi.

She grows 'Desi gehun' which gets sold at Rs 30 per Kg. She is also growing garlic, onions and goat feed. She uses urea, DAP and also *gobar-khaad*. She would like to switch to natural inputs but says that the soil is too conditioned to the Urea and DAP and so the transition cannot be immediate. When asked, when she thinks she can start the transition, she shares that having a proper fence is a priority as her efforts on the farm will be rendered useless if animals enter her field. Previously, she got a 100ft fence from CmF but requires 200-300ft more to cover her entire plot. CmF had also given her a vermicompost training but she has not yet started doing it.

She used to be a community support person for the FPO and had a salary of Rs 1,500 per month. There are about 55 shareholders in the FPO from her village and used to share a common tractor. However, the FPO has stopped procuring from their village for the past 1.5 years as they are skeptical of the quality and quantity the village can guarantee, due to constant disturbance caused by loose livestock that would enter the farmers' fields and spoil the produce.



When the FPO was still active, they used to take tomatoes and ladyfinger and their seeds from her. She estimates that if for 1 Kg, they would get a market price of Rs 200, then through the FPO the rate was Rs 300 per Kg.

Managing Diverse Sustainable Transitions

It is encouraging to find traditional practices still alive in Pindwara but at large, these must be documented. The presence of CmF and a strong FPO like Samruddhi, add to it the strong SHG network built by CmF over the years can pave the road to moving towards sustainable agriculture. However, It is important to acknowledge and address small local issues in farming to ensure sustainable transitions, as plural practices may be required for diverse farms. Women are considered natural leaders in facilitating transitions towards sustainable agriculture. However, the journey of resource farmers like Kalaram suggests that men can also play a significant role in this process.

Aneesh Mohan is a Research Assistant in the SFI project at IRMA.